

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश छवालियर
समक्ष : एम०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 375-एक/2015 - विरुद्ध आदेश
दिनांक 24-1-2015 - पारित बारा - अनुविभागीय
अधिकारी, सागर - प्रकरण क्रमांक 32 अ-27/2012-13

- 1- काशीराम पुत्र जमना पटैल
- 2- गिरधर पुत्र छोटेलाल पटैल
- 3- देवेन्द्र पुत्र छोटेलाल पटैल
- 4- पार्वती पत्नि स्व.छोटेलाल पटैल
- 5- तुलसीराम पुत्र काशीराम पटैल
सभी निवासी पालीवाल चक्की के पास
तिला, बाघराज बार्ड सागर

--आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- जंदकिशोर पुत्र गोरेलाल पटैल
धर्मदास वावा के पास तिली
बाघराज बार्ड सागर
- 2- रामनाथ पुत्र गोरेलाल
- 3- सुखलाल पुत्र रामनाथ पटैल
पालीवाल चक्की के पास
तिला, बाघराज बार्ड सागर
- 4- नवीन पुत्र नारायण प्रसाद पटैल
इन्द्रप्रस्थ कालोनी के सामने तिली रोड
बार्ड सागर तहसील व जिला सागर

----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री ओ०पी०शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 19-७-2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, सागर बारा
प्रकरण क्रमांक 32 अ-27/2012-13 में पारित आदेश दिनांक
24-1-15 के विरुद्ध म०प्र०भू राजस्व संहिता, 1959 की
बारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारोंश यह है कि आवेदक क्रमांक 1 ने अनावेदक क्रमांक 2 से 5 के विरुद्ध तहसीलदार सागर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पारिवारिक भूमि के शासकीय अभिलेख में बटवारे की मांग की, जिस पर अनावेदकगण ने आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार सागर ने हितबद्ध पक्षकारों को श्रवण कर प्रकरण क्रमांक 123अ-27/ 2009-10 में आदेश दिनांक 9-11-12 पारित किया तथा बटवारा फर्द तैयार कराकर पक्षकारों के बीच कब्जे अनुसार बटवारा करना स्वीकार किया। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक क्रमांक 2 एंव 3 ने अनुविभागीय अधिकारी, सागर के समक्ष अपील क्रमांक 47/अ-27/12-13 प्रस्तुत की। अपील प्रकरण में सुनवाई के दौरान आवेदकगण ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 41 नियम 27 का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अंतिम आदेश दिनांक 22-1-13 से स्वीकार किया एंव प्रकरण क्रमांक 32 अ-27/ 2012-13 के साथ सुनवाई हेतु संलग्न करने का आदेश दिया।

तहसीलदार सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 12 अ-27/ 2009-10 में पारित आदेश दिनांक 9-11-12 के विरुद्ध दूसरी अपील नंदकिशोर अनादेक क्रमांक-1 ने अनुविभागीय अधिकारी सागर के समक्ष प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 32 अ-27/ 2012-13 पर पंजीबद्ध हुई। प्रकरण में सुनवाई के दौरान काशीराम वर्गैरह के अभिभाषक ने म०प्र०भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 का आवेदन देकर बताया कि खसरा नंबर 45/3 रक्बा 1.70 एकड़ का बटांकन कराया गया, किन्तु प्रतिअपीलार्थी क. 6 व 7 को पक्षकार नहीं बनाया गया। खसरा नं. 45 के पूर्व में बटांकन किये गये हैं उज बटांकों के नवशा

(M)

PSC

में रकबा बड़ा दिया गया है। खसरा नं. 45/1, 45/4, 45/5 के लगभग 38 डिस्मल रकबा कम हो रहा है जिस कारण बटांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 24-1-15 पारित करके धारा 32 का आवेदन स्वीकार किया एंव प्रकरण तर्क हेतु नियत किया। इसी आदेश के विलम्ब यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अनुविभागीय अधिकारी सागर के अपील प्रकरण क्रमांक 47/अ-27/12-13 एंव अपील प्रकरण क्रमांक 32 अ-27/2012-13 में आये तथ्यों का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 24-1-15 एंव तहसीलदार सागर के प्रकरण क्रमांक 12 अ-72/2009-10 मे पारित आदेश दिनांक 9-11-12 के तुलनात्मक अध्ययन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 24-1-15 में धारा 32 का आवेदन स्वीकार निर्णीत किया है कि :-

“मेरे द्वारा उभय पक्षों के लिखित एंव मौखिक तर्कों का श्रवण किया गया। प्रति-अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नक्शा में सुधार किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः प्रति-अपीलार्थी का धारा 32 का आवेदन स्वीकार किया जाता है।”

तात्पर्य यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने धारा 32 का आवेदन स्वीकार कर प्रतिअपीलार्थी की नक्शा सुधार करने की मांग अप्रत्यक्ष रूप स्वीकार कर ली, जबकि दो अपील प्रकरणों का अंतिम निराकरण होना था। नक्शा सुधार कार्य मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धार 107 के अंतर्गत किया जाता है ऐंव इस धारा के अंतर्गत मूल न्यायालय कलेक्टर है इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 32 के आवेदन द्वारा नक्शा

(M)

PNL

सुधार की माँग एंव नक्शा सुधार का आवेदन अप्रत्यक्षरूप से स्वीकार करने में अधिकारिता-विहीन कार्य विज्ञा है जिसके कारण उनके द्वारा पारित अंतरित आदेश दिनांक २४-१-२०१५ स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

तहसीलदार सागर के प्रकरण क्रमांक १२ अ-७२/ २००९-१० मे पारित आदेश दिनांक ९-११-१२ के अवलोकन पर स्थिति यह है कि उन्होंने आदेश के अंत में निष्कर्ष दिया है कि :-

“प्रकरण में आये तथ्यों से पाया जाता है कि मौजा तिली माफी में भूमि खसरा नं० ४५/२ रकबा २.७० एंव खसरा नं० ४७/३ रकबा १०२५ उभय पक्षों के नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज है एंव पक्षकारों का आवेदन पत्र वर्णित अनुसार मौके पर बटवारा अनुसार कत्जा दर्ज है कब्जा अनुसार आवेदक खाता प्रथक प्रथक दर्ज कराना चाहता है। अतः म०प्र०भू राजस्व संहिता १९५९ की धारा १७८ के तहत मौजा तिली स्थित भूमि खसरा नं० ४५/२ रकबा २.७० ए० खसरा नं. ४७/३ रकबा १.२५ ए० का निम्नानुसार बटवारा कर खाता प्रथक प्रथक दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।”

तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट है कि उन्होंने मात्र खाता अलग अलग किया है जबकि पक्षकारों के बीच पूर्व से ही घरु बटवारा है एंव वह अपने अपने हिस्से की भूमि पर काविज होकर खेती करते आ रहे है तदनुसार ही तहसीलदार ने अभिलेख में अमल करते हुये खाता प्रथक करने के आदेश दिये हैं।

१. भू राजस्व संहिता, १९५९ (म०प्र०)- धारा १७८ - निजी ठहराव या व्यवस्था के अधीन आवेदन के पूर्व घरु (Private) बटवारा होकर अपने अपने हिस्सों पर काविज हैं तब आवेदक बराबरी का हिस्सा विभाजन की कार्यवाही करने की मांग नहीं कर सकता। (घुनाथ बनाम दिली १९७० रा०नि० ५९६ से अनुसरित)
२. भू राजस्व संहिता, १९५९ (म०प्र०)- धारा १७८ - पक्षकारों के मध्य मौखिक विभाजन - दुवारा विभाजन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा (१९८८ रा०नि० ९४ हाईकोर्ट)

-5- निग0प्र0क्ष0 375-एक/2015

उपरोक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार ब्दारा की गई खाता प्रथककरण की कार्यवाही उभय पक्ष के बीच पूर्व में हुये घरेलू बटवारे एंव मौके पर कब्जे, खेती करते चले आने के आधार पर आधारित है जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी सागर ने दोनों अपीलों में याहयता पर सुनवाई न करते हुये धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन की मांग अनुसार नक्शा सुधार करने की मांग अप्रयत्नप से स्वीकार करने में त्रुटि की है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी सागर ब्दारा अपील क्रमांक 47/अ-27/12-13 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 22-1-13 एंव अपील प्रकरण क्रमांक 32 अ-27/ 2012-13 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 24-1-15 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव तहसीलदार सागर ब्दारा प्रकरण क्रमांक 12 अ-72/ 2009-10 में पारित आदेश दिनांक 9-11-12 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

PK
NAC

(एम0क्ष0सिंह)
सदरस्य
राजस्व भण्डल
मध्य प्रदेश ज्वालियर